उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण

डॉ० अवध बिहारी सिंह*

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के व्यवहार में इच्छित सकारात्मक बदलाव लाती है। प्रभावी शिक्षा व्यक्ति के प्रवृत्ति कौशल ज्ञान एवं सोच में परिवर्तन लाने में सहायक है। मनुष्य के शारीरिक मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक स्तर पर विकास में शिक्षा की महती भूमिका है। शिक्षा हर तरह के अपेक्षित बदलाव एवं सुधार की धुरी होती है। किसी भी विकासशील समाज की शिक्षा रीढ़ होने के साथ ही उसके उत्थान एवं परिपक्वता का दर्पण होता है। शिक्षा से वंचित कोई भी व्यक्ति या समाज कभी भी अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं कर पाता है। ‘‘शिक्षा वह प्रकाश है जो मानव का जन्म से लेकर मृत्यु तक पथ प्रदर्शित करती रहती है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है। शिक्षा से ही मानव मनुष्यता को प्राप्त करता है। शिक्षा मानव, समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती है। शिक्षित तथा अशिक्षित मनुष्य में वही अन्तर है जो एक जलते हुए दीपक और बुझे हुए दीपक में होता है। जलता हुआ दीपक असंख्य बुझे हुए दीपकों को जलाता है। उसी प्रकार एक शिक्षित व्यक्ति असंख्य अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित कर सकता है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र में प्रर्याप्त मात्रा में ऐसा मानव संसाधन उपलब्ध हो जो राष्ट्र के प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का समुचित सदुपयोग कर सके। मानव संसाधनों के विकास में सर्वप्रथम स्थान शिक्षा का है। उच्च शिक्षा किसी भी देश की प्रगति का मूल आधार होती है। अर्थात उच्च शिक्षा द्वारा देश के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक विकास का आधार बिन्दु निर्धारित होता है। जिसका उद्देश्य मानवता, सहनशीलता, दूरदर्शिता तर्कपूर्ण विचारों का विकास, विभिन्न व्यवसायों का उत्कृष्ट प्रशिक्षण तथा सत्य की खोज करना। वस्तुतः एक सुसंस्कृत एवं उन्नतिशील समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में उच्च शिक्षा की महती भूमिका होती है।’’[1]

शिक्षा की प्रक्रिया तो मानव की उत्पतिकाल से ही आरम्भ हो गयी लेकिन उस वक्त उच्च शिक्षा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। प्रभावी ढंग से भारत में उच्च शिक्षा का प्रारम्भ पाँचवीं शताब्दी ईशा पूर्व से हुआ। उस वक्त पराविद्या और अपराविद्या का ज्ञान श्रवण, चिन्तन-मनन निदिध्यासन, प्रत्यक्ष, अनुमान, तर्कशक्ति से प्रदान किया जाता था। बौद्धकाल में तो बौद्ध बिहारों तथा मठों में ही उच्च शिक्षा का विकास हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी जिसके चलते इस काल में कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, जावा आदि देशों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के ध्येय से हिन्दुस्तान आते थे। अंग्रेजों के भाासन व्यवस्था में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना हुयी। जिससे मानवीय तथा व्यवसायिक शिक्षा की शुरूवात हुयी। सन् १८३५ में वैटिंग ने हिन्दुस्तानियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की भाुरूवात की। इसी समय से शिक्षा के वैश्वीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हो चला। सन् १८५३ तक तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य कायम हो चुका था। सन् १८५४ के आदेश पत्र द्वारा हिन्दुस्तान में मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। सन् १८८२ में हंटर आयोग ने सरकारी उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ निजी संस्थाओं की स्थापना की सलाह दी। १६०२ के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग तथा १६०४ के विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा उच्चतर शिक्षा में प्रचलित प्रणाली को मजबूती प्रदान की गयी। सन् १६१७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा हायर एजुकेशन में सुधार के निमित्त रचनात्मक नीति पर जोर दिया। इस तरह हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए काफी पहले से प्रयास जारी था लेकिन इसके मूल में १६वीं शताब्दी की लार्ड मैकाले की सिफारिशें भी थी। सन् १६२५ में इण्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गयी। जिसकी बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में पहचान कायम हुयी। इसके द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के मध्य भौक्षिक, सांस्कृतिक, अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाता था। देश को आजादी मिलने के बाद देश के नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं तथा उसमे सुधार के निमित्त सन् १६४८ में डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग ने देश की आजादी के पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमेटी के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसका एक अध्यक्ष तथा देश के बड़े शिक्षाविदों को इसका सदस्य नियुक्त करने की सलाह दी। उच्च शिक्षा के निमित्त स्थापित विश्वविद्यालय के दायित्वों के विषय में डॉ० राधाकृष्णन का यह कथन काफी प्रासंगिक है।‘‘The function of the university is not merely to send out Technically skilled and professionally competent men, but it is their duty to produce in them the quality which enables the individuals to treat one another in a truly democratic spirit’’[2].

उपरोक्त दायित्वों के सफल निर्वहन हेतु सन् १६५२ में सरकार ने केन्द्रीय तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहयोग से सम्बन्धित मसलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत लाने का निर्णय किया। २८ दिसम्बर १६५३ को शिक्षा मंत्री मौलान अबुल कलाम आजाद ने यू०जी०सी० की नींव रख दी लेकिन १६५६ में संसद में एक विशेष विधेयक लाकर इसे पूर्ण

***प्रवक्ता, जनसंचार विभाग, वी०बी०एस० पूर्वांचल वि०वि०, जौनपुर।**

रूप से स्थापित किया गया जिसका कार्य देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्यों के साथ ही विश्वविद्यालयों को यू०जी०सी० एक्ट १६५१ के तहत मान्यता प्रदान करना है। उच्च शिक्षा के प्रत्यायन कार्य में सहयोग हेतु यू०जी०सी० ने १५ परिशदों का गठन किया है।

यूपीए सरकार में शिक्षा बचाओ आन्दोलन समिति के सयुक्त सचिव तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव श्री अतुल कोठारी के अनुसार सन १६४७ में भारत में १८ विश्वविद्यालय, ५१८ महाविद्यालय, २४,००० शिक्षक तथा २,२८,८८१ छात्र थे। वहीं सन् २००६ में ५०४ विश्वविद्यालय, २५,६५१ महाविद्यालय, ५,८५,००० शिक्षक तथा १३६.४२ लाख छात्र थे। विकीपीडिया के अनुसार भारत में इस समय ४५ केन्द्रीय, ३२२ राज्य, १२८ डीम्ड तथा १६२ निजी विश्वविद्यालय हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ६२ विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। यू०जी०सी० के अनुसार भारत जैसे विशाल देश में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए सन् २०१५ तक आधुनिक शोध सुविधा सम्पन्न १५०० और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होगी। शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में यूनेस्को का कथन है कि-'' शिक्षा दृष्टिकोण विस्तृत करने और कौशल बढ़ाने की वह सुनियोजित प्रक्रिया है जो स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक तथा राजनीतिक बदलाव सभी देशों के लिए और खासतौर से उन विकासशील देशों के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी जनता के हर वर्ग की मूल आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आमूल-चूल परिवर्तन लाने को प्रयत्नशील हैं।-''[3]

भारत में आजादी से पहले मानवीय मूल्यों की स्थापना, संस्कृति एवं सभ्यता के विकास और युवाओं के स्वावलम्बन हेतु मिशनरी भावना से प्रेरित होकर देशभक्तों महापुरूषों समाजसेवीयों द्वारा भिक्षाटन करके तथा दान मांग कर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना जैसा पुनीत कार्य किया जाता था। उनका यह कार्य समाज एवं राष्ट्र के उन्नयन भाव से प्रेरित होता था इस सन्दर्भ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के संस्थापक भारत रत्न पं० मदन मोहन मालवीय जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। देश के युवाओं को स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हे विभिन्न कलाओं तथा विज्ञानों की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मालवीय जी की निष्ठा एवं उनके अध्यवसाय की प्रशंसा करते हुए डॉ० एनी बेसेन्ट ने कहा था- ''मालवीय जी ने अपना समस्त सांसारिक जीवन, अपनी शक्ति, अपनी प्रबल भाषण कला, यहाँ तक कि स्वयं अपने को और अपने स्वास्थ्य को इस महान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए बलिदान कर दिया है।''[4]

आजादी के बाद मिशनरी भावना की हर क्षेत्र में कमी आयी। इससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी अछूती नही रही। पहले शिक्षा का दान महादान समझकर देश के मनीषी, युगद्रष्टा, राष्ट्रनेता युवाओं के विकास, स्वावलम्बन तथा देश की उन्नति के लिए उच्च शिक्षा के विकास के लिए कालेज तथा विश्वविद्यालय की स्थापना करना महान कर्तव्य एवं दायित्व मानते थे। इसके कार्य हेतु अपना सर्वस्व समर्पित कर देते थे। आजादी के कुछ वर्षों बाद शिक्षा का व्यवसायीकरण शुरू हो गया। यह मुनाफा कमाने का एक अच्छा माध्यम लोगों को नजर आने लगा। पिछले दो दर्शकों से तो यह कालेधन को सफेद करने का सबसे अच्छा साधन होता जा रहा है। अधिकांश मंत्री, सांसद, विधायक, उद्योगपति, ठेकेदार, माफिया, भट्ठा मालिक, भ्रष्ट अधिकारी स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग संस्थान, एम.बी.ए., बी.फार्मा, स्कूल तथा मेडिकल कालेज खोलना शुरू कर दिए हैं। सरकारी तंत्र में अपने रसूख तथा पैसा के बल पर बिना मानक पूर्ण किये हुए आसानी से उच्च शिक्षण संस्थायें खोलते जा रहे हैं। शैक्षणिक, छात्रावास तथा प्रायोगिक शुल्क के नाम पर मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। वहीं स्ववित्तपोषित योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों का लगातार शोषण किया जा रहा है। कुछ कालेजों को छोड़कर अधिकांश कालेजों में तीन हजार से आठ हजार रूपये प्रतिमाह शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। वह भी केवल ८ से १० महीने तक। इस न्यूनतम धनराशि में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक किसी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन कर पा रहा है। इसके चलते वे मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। जिससे उनका शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकारी/अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों/प्रचार्यो की चयन प्रक्रिया में पैसा एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लाखों का चढावा चढ़ाकर चयनित शिक्षकों/प्राचार्यों से कतर्व्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने की आशा भी बेमानी है। अनुदानित कालेजों के प्रबन्ध तंत्र पर ऐसे लोगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है जिनका शिक्षा से कोई नाता नहीं है। ऐसे लोग महाविद्यालयों को अपने ऐशो-आराम तथा धन उगाही केन्द्र बनाते जा रहे हैं। अब तो विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी लोगों की उंगली उठने लगी हैं।

जब से केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों ने उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं बेरूखी दिखाना शुरू किया है तब से शिक्षा में हर स्तर पर लगातार गिरावट जारी है। इसके मूल कारण का जिक्र करते हुए एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जगमोहन राजपूत ने लिखा है कि ''शिक्षा के लिए जीडीपी के छह प्रतिशत आवंटन के वायदे अनेक दशकों से होते आ रहे हैं मगर यह चार प्रतिशत से कम ही रहता है। केन्द्र द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अनेक अन्य महत्वपूर्ण संस्थान भी संसाधनों की कमी को ही शोध तथा नवाचार के लिए बड़ा अवरोध मानते हैं। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान गाना कठिन नही है। केन्द्र सरकारों तथा राज्य सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता पर निगाह रखने के लिए जो संस्थायें बनाई है उनकी साख लगातार गिरती रही है।''[5]

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, अनुदानित महाविद्यालयों, तथा राजकीय महाविद्यालयों में विगत कुछ वर्षो से काफी तादात में शिक्षक सेवा निवृत हो रहें तथा कुछ पद पहले से ही खाली पड़े है जिन पर वर्षो से नई नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। जिसके चलते विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं। इससे उच्च शिक्षा का पठन-पाठन एवं शोध कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। इसके कारण छात्रों में असंतोष भी बढ़ रहा है। इससे सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं संस्थानों में शिक्षक बनने से युवाओं का मोह भी भंग होता जा रहा है। इस सन्दर्भ में आनन्द कुमार ने लिखा है- ‘‘अगर हम यूजीसी के आकड़ों पर गौर करें तो विभिन्न महाविद्यालयों को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए लगभग १४ लाख शिक्षकों की तत्काल जरूरत है। मानव संसाधन मंत्रालय के आकड़ों के अुनसार यूपी में तीन लाख, बिहार में २.६ लाख और पश्चिम बंगाल में एक लाख स्कूली शिक्षकों की कमी है।”[६]

मुक्त बाजार तथा आर्थिक उदारीकरण नीति से भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था काफी प्रभावित हुयी है जिसके चलते स्ववित्त पोशित शिक्षा व्यवस्था के तहत उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढावा मिल रहा है। इससे पूँजीपतियों के लिए कालेधन के निवेश एवं मुनाफा खोरी का अवसर मिलता जा रहा है। उच्च शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश के निर्णय ने भारत में उच्च शिक्षा की विदेशी डिग्री बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। इन नीतियो से शिक्षा की समानता के अधिकार, शिक्षा सबका अधिकार जैसे लोक कल्याणकारी योजना को अमल मे लाने के बजाय सरकार ने उच्च शिक्षा को पूँजीपतियों के दुकानों के हवाले कर दिया है। इससे सरकारी व्यवस्था के तहत चलने वाले कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के प्रति युवाओं का आकर्षण कम होता जा रहा है। अच्छी खासी पूॅंजी खर्च करके बनाये गये आधुनिक सूचना तकनीक से लैश, नवीनतम सुख-सुविधा वाले आलीशान निजी संस्थानों /कालेजों /विश्वविद्यालयों सें उच्च शिक्षा प्राप्त करना युवाओं का सपना बनता जा रहा है। इस सपना को साकार करने हेतु उन्हे अच्छी खासी रकम अदा करनी पड़ रही है । बड़े बड़े शहरो में ऊँची कीमत पर उच्च शिक्षा को बेचने की दुकानें लगातार खुलती जा रही हैं। शिक्षा को एक उत्पाद के रूप में बेचने हेतु लगातार मीडिया में इन संस्थानों द्वारा विज्ञापन भी दिया जा रहा है । इस तरह से आम व्यवसाय की तरह ही उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण लगातार चल रहा है। शिक्षा के बाजारीकरण पर असंतोश व्यक्त करते हुये प्रदेश के कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्री राम नाईक ने बीएचयू के अपने उद्बोधन में कहा‘‘आज कल छात्र और शिक्षक विश्वविद्यालयों के बजाय कोचिंग व निजी संस्थानों मे शिक्षा लेने-देने जाते हैं । सारा खेल पैसों का हो गया है।”[७]

सन्दर्भ ग्रंथः-

१. शर्मा डॉ० अवधेश कुमार (२०१४)ः उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबन्धनः मूल्यांकन एवं प्रत्यापन, शोध प्रेरक, आई.एस.एस.एन. २२३१-४१३ x वा. IV इशू २, पृष्ठ-१।

२. गतिमान-२०१३, वी.बी.एस. पूर्वान्चल वि० विद्यालय, जौनपुर, पृ०-२२।

३. विलानिलम जे.वी.ः भारत में शिक्षा व्यवस्थाः१९४७-२०१२, योजना, अगस्त २०१२, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ०-२८।

४. चतुर्वेदी सीताराम,ः आधुनिक भारत के निर्माता पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, १९८०, पृ० ६७।

५. राजपूत जगमोहन सिंहः तलाशने होंगे सच्चे आयाम, दैनिक जागरण, वाराणसी, २१ दिसम्बर २०१४, पृ० ११।

६. कुमार आनंदः तो युवा क्यों सपने पाले शिक्षक बनने के, दैनिक जागरण, वाराणसी, २१ दिसम्बर २०१४, पृ० ११।

७. दैनिक जागरण, वाराणसी, १५ दिसम्बर २०१४, पृ०-६।

******